(e) if so, the details of the works so awarded;

(f) the reasons for not giving contracts on tenders; and

(g) the action taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P. K. THUNGON): (a) and (b) DDA has reported that the following two complaints have been reported:—

(i) tenders of peripheral storm drain in Sector B-4 Narela opened on 29-1-94 were reported pooled (collusive bids) under threat from the bad elements.

(ii) tenders for the work of maintenance of Majnu Ka Tila Sub-Head : Removal of refuse and mulba opened on 16-7-94 were reported to have been grabbed by the other intending tenderer and put into the tender box.

(c) Tenders have been rejected in ihe case of (i) above and DDA is already seized with the complaint at (ii) above.

(d) to (g) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बड़े भवन निर्माताओं को भूमि का आवंटन

681. श्री आस मोहम्मद:
श्री ईश दत्त यादव :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बड़े भवन-निर्माताओं को भूमि आवंटित की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें उक्त भूमि किस-किस दरों पर आवंटित की गई है ;

(ग) क्या इस बीच भूमि का लागत मूल्य भी वसूल किया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उनमें से प्रत्येक भवन निर्माता से वसूल की जाने वाली बकाया धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियमावली, 1981 के अनुसार वाणिज्यिक भूखण्ड निजी भवन निर्माताओं की खुली नीलामी अथवा निविदाएं आमंत्रित कर आवंटित किया जा सकता है । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि पिछले तीन वर्षों (1991-92, 1992-93 तथा 1993-94) के दौरान 139 वाणिज्यिक भूखण्ड खुली नीलामी और निविदाएं आमंत्रित कर बेचे गए थे ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान नीलामी/निविदाओं के माध्यम से बेचे गए 139 वाणिज्यिक भू-खण्डों, आकार सहित भूखण्डों की संख्या, फर्श क्षेत्र, सेन्टर और प्राप्त धनराशि आदि के ब्यौरे अनुपत्र में दिए गए हैं । (देखिये परिशिष्ट 171, अनुपत्र संख्या 17)

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) कोई बकाया धनराशि नहीं है ।

Distribution of funds under Nehra Roggar Yojana

682. SHRI RAMACHANDRAN PILLAI:

SHRIE. BALANANDAN:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government used discriminatory standards in the distribution of funds under the Nehru Rozgar Yojana to States; and

(b) if so, what action has been taken on such practices as mentioned in the Comptroller and Auditor General (C&AG) Report?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P. K. THUNGON): (a) No, Sir. However the allocations were moderated due to non-performance and funds were converted to the better performing States/U.Ts.

(b) The Comptroller & Auditor General (C&AG) has been appraised the above position.

दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों को आवासों का आबंटन

683. श्री रामेश्वर पासवान : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सरकारी आवास का आबंटन बारी से ज्यादा बिना बारी का होता है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार क्रमशः कितने सरकारी आवास बारी आने पर आबंटित किए गए तथा कितने बिना बारी के आबंटित किए गए ;

(ग) क्या सरकारी आवासों के आबंटन के संबंध में कोई स्पष्ट नीति निर्धारित है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) और (घ) साधारण पूल में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास का आबंटन, सरकारी आवास का आबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) नियमावली, 1963 में निर्धारित प्रावधानों के तहत शासित होता है ।

Allotment of DDA Flats

684. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: SHRI VIRENDRA KATARIA:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Comptroller and Auditor General of India has revealed that nearly 50,000 people are awaiting allotment of DDAflats during the past more than a decade;

(b) if so, whether it is a fact that thousands of DDA flats which are ready and lying vacant for allotment;

(c) if so, the details thereof;

(d) what are the details of the irregularities noticed by CAG in the allotment of DDA flatst; and

(e) what are the further steps Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P. K. THUNGON): (a) Yes, Sir. According to the DDA, at present, 32,663 persons are on the waitlist for allotment of DDA flats under the New Pattern Registration Scheme, 1979.

(b)and(c) Allotment of flats is a continuous process and flats are allotted to registrants soon after they are completed. However, the flats surrendered by allottees on cancelled by DDAfor non fulfilment of the terms and conditions of allotment remain vacant until re-allotment to the next registrants of the waiting list. Some houses are vacant for want of full payment and provision of complete documents.

(d) and (e) DDA flats are generally allotted through computer based draws to avoid any irregularity in